जाति नहीं योग्यता के आधार पर हो आरक्षण

लखनऊ ,16 नवंबर (ए)। प्रतापगढ़ के कुंडा से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने शुक्रवार को नई राजनीतिक पार्टी के गठन का ऐलान किया। हालांकि पार्टी का नाम अभी तय नहीं है। शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में राजा भैया ने बताया कि चुनाव आयोग को तीन नाम भेजे गए हैं। हालांकि चर्चा है कि राजा भैया अपने दल का नाम 'जनसत्ता पार्टी' रखेंगे। उधर, राजा भैया ने प्रेस वार्ता में एससी-एसटी ऐक्ट को लेकर सवाल भी खड़े किए।

पार्टी गठन की जानकारी देने के लिए बुलाए गए प्रेस वार्ता में राजा भैया ने आरक्षण के मुद्दे को भी जोर-शोर से उठाया। राजा भैया ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण लोगों को हतोत्साहित करता है। उन्होंने कहा कि योग्यता के आधार पर आरक्षण होना चाहिए।

एससी-एसटी ऐक्ट पर केंद्र को घेरते हुए राजा भैया ने कहा कि यह कदम न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले में पहले विवेचना और उसके बाद ही गिरफ्तारी होनी चाहिए।

30 नवम्बर को करेंगे रैली

इस दौरान राजा भैया ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान एससी-एसटी ऐक्ट और आरक्षण में प्रमोशन का विरोध उनकी पार्टी का मुख्य मुद्दा होगा। प्रेस वार्ता में राजा भैया ने 30 नवम्बर को लखनऊ के रमाबाई मैदान में रैली आयोजित करने की भी जानकारी दी। माना जा रहा है कि इसी रैली के जरिए राजा भैया 2019 लोकसभा चुनाव का आगाज भी करेंगे।

बीजेपी का इशारा तो नहीं!

चर्चा यह भी है कि राजा भैया द्वारा नई पार्टी के गठन के पीछे बीजेपी के शीर्ष नेताओं का ही इशारा है। तर्क है कि राजा राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। वर्तमान में बीजेपी से पंगा लेना उनके लिए हितकर नहीं है। ऐसे में नई पार्टी का गठन कर जहां बीजेपी से नाराज वोट बैंक को थाम सकते हैं, वहीं ऐसे नेताओं को भी लामबंद कर सकते हैं जो एसपी और बीएसपी से नाराज चल रहे हैं। चुनाव के बाद वह प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के साथ जा सकते हैं। बीजेपी की पूरी कार्य योजना एसपी-बीएसपी के महागठबंधन की काट के लिए चल रही है। ऐसे में राजा भैया की पार्टी से मैदान में उतरे प्रत्याशी कई सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की राह आसान कर सकते हैं।

1971 से पहले असम आने वालों को एनआरसी में शामिल किया जाएगा : एसओपी

नई दिल्ली, 16 नवम्बर (ए)। वर्ष 1971 से पूर्व असम आने वाले वैसे भारतीय नागरिकों को एनआरसी में शामिल किया जाएगा अगर उनके दावे और आपत्तियों के निस्तारण के दौरान ऐसे लोगों की नागरिकता का निर्धारण निस्संदेह तरीके से हो जाता है। यह मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का हिस्सा है, जिसे राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के प्रदेश समन्वयक प्रतीक हजेला ने उच्चतम न्यायालय को सौंपा है। उच्चतम न्यायालय ने एनआरसी में नामों को शामिल करने के लिए दावा और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 15 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है। एसओपी दायर करते समय एनआरसी समन्वयक ने कहा कि ऐसे दृष्टांत हैं जहां कुछ लोग 24 मार्च 1971 से पूर्व भारत के किसी हिस्से में (असम से बाहर) में अपने निवास के बारे में संतोषप्रद दस्तावेज मुहैया कराने में सक्षम हैं। ऐसे में उनके मामले पर नागरिकता (नागरिकों के पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 की नियम संख्या चार और इसकी अनुसूची की धारा 3 (3) के तहत विचार किया जाएगा।

उत्तर कोरिया ने नये हाई-टेक हथियार का परीक्षण किया : रिपोर्ट

सियोल, 16 नवम्बर (ए)। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने नये 'हाई टेक' हथियार के परीक्षण का निरीक्षण किया। योनहाप संवाद समिति के अनुसार प्योंगयांग की सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उत्तर कोरिया के सरकारी प्रसारक का हवाला देते हुए योनहाप ने बताया, ''किम जोंग उन ने राष्ट्रीय रक्षा विज्ञान अकादमी में नव विकसित हाई-टेक सामरिक हथियार के परीक्षण का निरीक्षण किया।'' उसने बताया कि परीक्षण सफल रहा, लेकिन यह किस तरह का हथियार है, इस बारे में नहीं बताया। यह हमारे देश की रक्षा को अभेद्य बनाता है और हमारी पीपुल्स आर्मी की लड़ाकू शक्ति को मजबूत बनाता है।'' प्योंगयांग द्वारा परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण रोका जाना इस साल के कूटनीतिक घटनाक्रमों और उत्तर कोरिया-अमेरिका के बीच वार्ता के लिये महत्वपूर्ण रहा है।

सपना चौधरी के इवेंट में भीड़ हुई बेकाबू, बवाल में एक की मौत

बेगूसराय ,16 नवंबर (आरएनएस)। रियेलिटी शो बिग-बॉस से देशभर में मशहूर हुईं हरियाणा की डांसर सपना चौधरी के एक कार्यक्रम के दौरान भारी बवाल हो गया। बिहार के बेगूसराय में छठ पर आयोजित एक कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घटना में एक शख्स की मौत की आशंका है। हालांकि, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि इससे पहले भी सपना चौधरी के कार्यक्रमों में कई बार भीड़ बेकाबू होने से विवाद हुआ है।

अभी तक मिली जानकारी के अनुसार बिहार के बेगूसराय जिले में छठ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें सपना भी शिरकत करने वाली थीं। सपना को देखने के लिए भाड़ी भीड़ उमड़ी थी। बताया जाता है कि सपना का डांस शुरू होने के साथ ही लोग बेकाबू होने लगे और स्टेज की ओर भागने लगे। इसी में वहां भगदड़ मच गई।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ीं। आशंका जताई जा रही है कि पूरे बवाल के दौरान एक शख्स की जान चली गई। हालांकि, इस बारे में अधिकारियों की ओर से अभी पुष्टि नहीं की गई है। बता दें कि इससे पहले भी कई बार सपना के कार्यक्रमों में बवाल मचा है और कई कार्यक्रम रद्द भी करने पड़े हैं।

प्रदूषण में सुधार, हवा अब भी खराब

नई दिल्ली, 16 नवम्बर (ए)। दिल्ली-एनसीआर में बुधवार रात हुई बारिश के बाद वातावरण में छाए प्रदूषण के स्तर में तेजी से गिरावट आई है। इसके बावजूद हवा खराब ही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट के मुताबिक वीरवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) स्तर 217 रहा, जो कि 'खराब' श्रेणी में आता है। पड़ोसी शहर गाजियाबाद का स्तर 264, फरीदाबाद का स्तर 266, नोएडा का स्तर 229, ग्रेटर नोएडा का स्तर 236 व गुरुग्राम का स्तर 162 रहा। बोर्ड द्वारा जारी देशभर के बड़े शहरों पर आधारित रिपोर्ट में सिर्फ पटियाला में स्वच्छ सांस लेने वाली हवा है, यहां एक्यूआई स्तर 40 रहा। दिल्ली में दीपावली के बाद 'बहुत खराब' और 'गंभीर' श्रेणियों के बीच हवा की गुणवत्ता घटती-बढ़ती रही है। मौसम विज्ञान संस्थान के मुताबिक पीएम 2.5 सांद्रता में अगले दो दिनों में सुधार आएगा। पर्यावरणविदों का कहना है कि थोड़ी-बहुत बारिश से दिल्ली के वायु प्रदूषण में कमी आई है, यदि एक-दो दिनों में तेजी से और देर तक बारिश हो तो हालात और बेहतर हो सकते हैं।

स्कूली बच्चों से वायु प्रदूषण पर अध्ययन करेगा एम्स : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली में दमे से ग्रस्त स्कूली बच्चों को कलाई पर पहने जा सकने वाले सेंसर देगा, जो उनके आसपास के वायु प्रदूषण पर लगातार नजर रखेंगे। एम्स के सहायक प्रोफेसर डॉ. करन मदान ने कहा कि ये प्रदूषण सेंसर हल्के हैं और कमर पर भी आसानी से पहने जा सकने वाले हैं। ये पूरे दिन आसपास के वायु प्रदूषण पर जरूरी जानकारी संग्रहित करेंगे।

बच्चों को एक सप्ताह के लिए दिए जाएंगे सेंसर : आईआईटी-दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन व चेन्नई के श्री रामचंद्र विश्वविद्यालय के साथ मिलकर कराए जा रहे अध्ययन के तहत बच्चों को एक सप्ताह के लिए ये सेंसर दिए जाएंगे। मदान ने कहा कि ये उच्च गुणवत्ता वाले सेंसर हमें इस बारे में जानकारी देंगे कि कोई बच्चा स्कूल में, रास्ते में या घर पर कितने वायु प्रदूषण के संपर्क में आता है। इससे हमें उनके स्वास्थ्य पर पडने़ वाले असर का पता लगाने में मदद मिलेगी। एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया के अनुसार अगर जरूरी हुआ तो सेंसर को लंबी अवधि के लिए भी बच्चों के साथ रखा जा सकता है।

मैकेनिकल उपकरण से दूर होगा कचरा : बागवानी विभाग ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों में पार्कों के रख-रखाव नर्सरियों और हरित कचरा प्रबंधन केंद्रों में बड़े पैमाने पर मशीनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। स्थायी समिति की अध्यक्ष शिखा राय ने वीरवार को ग्रेटर कैलाश-1 की एक नर्सरी में मैकेनिकल उपकरणों के उपयोग कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक श्रेरडर चिपर मशीन, लीफ पिकर मशीन, हैज ट्रिमर प्रबंधन केंद्रों में भी इन मशीनों का इस्तेमाल उपयोगी सिद्ध होगा। इस दौरान बागवानी विभाग के निदेशक डॉ. आलोक सिंह भी मौजूद रहे। लीफ पिकर मशीनें तेजी से पार्कों और सड़कों से पश्रे अपने भीतर एकत्रित कर लेती हैं और इन्हें आधुनिक श्रेरडर-चिपर मशीनों में डाल कर कुछ मिनट में महीन बना दिया जाता है। महीन बनाए गए पश्रों का तुरंत क्यारियों में डाल कर खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पहले चरण में 10 नई लीफ पिकर मशीनें और 10 नई आधुनिक श्रेरडर मशीनें प्राप्त की जा रही है जिनमें से कुल 14 मशीनें प्राप्त कर ली गई है।

पराली जलाने में यूपी भी चला पंजाब हरियाणा की राह,केंद्रीय एजेंसियों ने दिया निर्देश

नई दिल्ली, 16 नवम्बर (ए)। खेतों में पराली जलाने की पंजाब व हरियाणा की बीमारी से अभी सिर्फ दिल्ली और एनसीआर की ही सांस फूल रही है। अब यह बीमारी तेजी से उत्तर प्रदेश में भी फैल रही है जिस पर समय रहते अंकुश नहीं लगा तो इसके जहरीले धुएं की चपेट में उत्तर प्रदेश के बड़े शहर सहित पड़ोसी राज्य भी आने में देर नहीं लगेगी।

वैसे प्रदूषण के मामले में अभी भी यूपी के कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ और वाराणसी जैसे शहरों की स्थिति काफी खराब है। जहां प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ रहता है। पराली के जहरीले धुएं से दिल्ली को बचाने में जुटी केंद्रीय एजेंसियों ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की बढ़ी घटनाओं को देख हैरानी जताई है।

खासबात यह है कि पराली जलाने की यह बीमारी उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों में भी पहुंच गई है, जहां अब तक धान की कटाई नीचे से ही होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से फसलों की कटाई के लिए मजदूरों की समस्या बढ़ी है, उसमें ज्यादातर किसान मशीनों से कटाई कराने को ही तवज्जो दे रहे है।

बाद में वह फसल के बाकी बचे हिस्से को आग के हवाले कर देते है। पराली जलाने की बढ़ी हुई घटनाओं को लेकर केंद्रीय एजेंसियों ने हाल ही में राज्य को सतर्क किया है। इसके रोकथाम को लेकर तेजी से कदम उठाने के निर्देश दिए है।

पराली प्रबंधन पर काम कर रही केंद्रीय टीम के मुताबिक उत्तर प्रदेश में यह समस्या फिलहाल 71 जिलों में फैल चुकी है, जहां धीरे-धीरे इनमें बढ़ोतरी हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 में करीब 12-13 लाख टन के आसपास पराली जलाने की घटनाएं देखी गई थी। वह इस बार बढ़कर 20 लाख टन तक पहुंच गई है।

उत्तर प्रदेश को इसकी रोकथाम के लिए वर्ष 2018-19 में तकरीबन 150 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। इसकी मदद से किसानों को पराली खेतों में ही जलाए बगैर नष्ट करने के लिए मशीन उपलब्ध करानी थी। किसानों को इससे होने वाले नुकसान को लेकर जागरूक करना था।

कुवैत में तूफान : घिरे मप्र के श्योपुर से गए 700 से ज्यादा मजदूर

श्योपुर, 16 नवम्बर (ए)। खाड़ी देश कुवैत में बुधवार-गुरुवार को तेज हवा के साथ पड़े ओले व पानी ने पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस तूफान में मप्र के श्योपुर के करीब 700 से ज्यादा मजदूर भी फंसे हुए हैं। जिन स्थानों पर श्योपुर के मजदूर रह रहे हैं, उसके आसपास चारों ओर पानी भरा हुआ है। कुवैत में रह रहे मो. इख्तियार खान (पिंटू) ने बताया कि दो दिन से तेज बारिश हो रही है और हवा चल रही है। श्योपुर के सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन तूफान से खाने-पीने का संकट आता जा रहा है। शहर से बाहर निकलने का एक मात्र रास्ता हवाई अड्डा है, जिसमें पानी भर गया है। स्टोर में रखी सब्जियां, फल, पानी आदि भी खत्म होते जा रहे हैं।

सीवीसी की रिपोर्ट में आलोक वर्मा को क्लीनचिट नहीं

नई दिल्ली ,16 नवंबर (ए)। राफेल के बाद गर्माया सीबीआई विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई जिसमें कोर्ट ने सीवीसी रिपोर्ट की कॉपी सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को देने का आदेश दिया, जिस पर उन्हें सोमवार तक जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। 12 नवंबर को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी थी। जिसमें और अधिक जांच की जरूरत बताई गई है।

रिपोर्ट में सीवीसी ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को क्लीनचिट नहीं दी गई है। उनपर कुछ और आरोप हैं जिनकी जांच जरूरी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आदेश नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने साथ ही आलोक वर्मा से सीलबंद लिफाफे में जवाब मांगे हैं। सीवीसी ने छुट्टी पर भेजे गए आलोक वर्मा के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की है। ध्यान रहे कि सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। जिसके बाद सरकार ने दोनों को छुट्टी पर भेज दिया था। इस मसले को अलग-अलग याचिकाओं के जरिए कोर्ट में रखा गया है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को सूचित किया कि 10 नवंबर को पूरी हुयी जांच की निगरानी शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एके पटनायक ने की। प्रधान न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि रजिस्ट्री रविवार को खुली थी परंतु उसे रिपोर्ट दाखिल करने के बारे में कोई सूचना नहीं दी गयी। सॉलिसीटर जनरल ने बाद में क्षमा याचना की और कहा कि वह रिपोर्ट दाखिल करने में उनकी ओर से हुये विलंब की परिस्थितियों पर स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं।

देश में पहले बच्चे को किए गए सफल लिवर प्रत्यारोपण के पूरे हुए 20 साल

नई दिल्ली, 16 नवम्बर (ए)। देश में पहले बच्चे को किए गए लिवर प्रत्यारोपण के 20 साल पूरे हो गए। 20 महीने की उम्र में तमिलनाडु के कांचीपुरम के रहने वाले संजय कंदासामी नामक बच्चे को अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों ने लिवर प्रत्यारोपण किया था। वह अब 21 साल के हो चुके हैं। इसके साथ ही अब सफल लिवर प्रत्यारोपण भी सामान्य बात हो गई है पर यह सर्जरी अब भी महंगी है। हालांकि अब मरीजों की आर्थिक मदद के लिए अब बड़ी संख्या में लोग आगे आ रहे हैं। इसलिए अपोलो अस्पताल में पिछले दो साल में करीब 50 फीसद मरीजों का लिवर प्रत्यारोपण दान के पैसे से किया गया है। अपोलो अस्पताल के मेडिकल निदेशक डॉ. अनुपम सिब्बल ने कहा कि लिवर प्रत्यारोपण पर करीब 18 लाख रुपये खर्च आता है। पिछले दो साल में अस्पताल में 57 मरीजों को लिवर प्रत्यारोपण किया गया है। जिसमें 27 मरीजों का प्रत्यारोपण किसी की आर्थिक मदद से किया गया है। वर्तमान समय में अनेक संस्थाएं मरीजों की मदद के लिए काम कर रही हैं। सोशल मीडिया भी मरीजों के लिए पैसा एकत्रित करने का बड़ा माध्यम साबित हो रहा है। दिक्कत यह है कि ज्यादातर मरीजों को उपयुक्त डोनर नहीं मिल पाते। यह इलाज में सबसे बड़ा बाधक है। वर्तमान समय में हर साल करीब दो हजार बच्चों व 18,000 हजार वयस्कों को लिवर प्रत्यारोपण की जरूरत होती है। जबकि हर साल करीब 1800 प्रत्यारोपण हो पाता है। उन्होंने कहा कि 18 नवंबर 1998 को संजय का लिवर प्रत्यारोपण किया गया था। उनके पिता ने उन्हें लिवर दान किया था। लिवर एक ऐसा अंग है जो जीवित व्यक्ति के दान करने पर उसका 90 फीसद हिस्सा करीब 12 सप्ताह में दोबारा वापस विकसित हो जाता है। क्रिकेटर गौतम गंभीर ने ब्रेन डेड डोनर प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने की अपील की।

मीटू की चपेट में ऑल इंडिया रेडियो, मेनका गांधी ने की जांच की मांग

नई दिल्ली, 16 नवम्बर (ए)। देश में इन दिनों मीटू अभियान की लहर है। इसके ज़रिये सैकड़ों महिलाएं खुद के साथ हुए यौन दुर्व्यवहारों की घटनाएं सोशल मीडिया पर ज़ाहिर कर चुकी हैं। इनमें कई दुर्घटनाएं उनके साथ कार्यस्थल पर हुई हैं। पिछले कुछ समय से ऑल इंडिया रेडियो में यौन शोषण के कई मामले सामने आए हैं, जिन्हें लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जांच की मांग की है।

महिला कर्मचारियों ने बताई आपबीती : खबरों के अनुसार, ऑल इंडिया रेडियो के कई स्टेशनों से यौन शोषण के मामले सामने आए हैं। ये मामले अधिकतर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली महिला कर्मचारियों के साथ ही हुए हैं। इनमें से कुछ महिलाएं यहां दो दशकों से काम कर रही थीं, लेकिन शिकायत करने के बाद से अब उन्हें काम नहीं दिया जा रहा है। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो कैजुअल अनाउंसर एंड कम्पेयेर्स यूनियन ने मेनका गांधी को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद उन्होंने केंद्रीय राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मामले में जांच करने को कहा है।

ब्रेक्जिट मुद्दे पर घमासान जारी, 2 और मंत्रियों ने दिया इस्तीफा

लंदन, 16 नवम्बर (ए)। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच ब्रेक्जिट मुद्दे पर चल रहा घमासान जारी है। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के वार्ताकारों में ब्रेक्जिट समझौते की रूपरेखा पर सहमति बनने के बाद बुधवार को जब इसकी समीक्षा के लिए कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई तो इसमें काफी गहमागहमी का माहौल रहा। पांच घंटे चली मैराथन बैठक के बाद प्रधानमंत्री थेरेसा मे को सांसदों की आलोचना का शिकार होना पड़ा। लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने अपनी कुर्सी और कैबिनेट को बचा लिया है।

इस बैठक में डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी काफी उग्र दिखाई दी। पार्टी की तरफ से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने तक की बात कह डाली। आलम ये है कि ईयू ड्राफ्ट के खिलाफ ब्रेक्जिट सेक्रेट्री डोमेनिक राब, सेक्रेट्री ऑफ स्टेयट फॉर वर्क एंड पेंशन ईस्थ र मेकवे समेत दो और जूनियर मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले दो और मंत्री भी इसी मुद्दे पर इस्तीफा दे चुके हैं। लेबर पार्टी के नेताओं ने भी यह साफ कर दिया कि सरकार साफ करे कि वह किसके पक्ष में है। जेरेमी कॉरबेन ने यहां तक कहा कि उन्हें इस समझौते में कोई विश्वास नहीं है। बता दें कि ईयू और ब्रिटेन के बीच करीब 585 पेज का एक दस्तावेज तैयार किया गया है जिसको देश के हित में बताया जा रहा है। फिलहाल इसको लेकर जबरदस्त घमासान मचा है। थेरेसा पहले ही कह चुकी हैं कि वह कोई भी फैसला देशहित में ही लेंगी। ऐसा कोई भी कदम जिससे देश को नुकसान हो वह नहीं उठाने वाली हैं और न ही देश के बंटवारे का घातक कदम वह उठाएंगी।

संयुक्त राष्ट्र सचिवालय स्टाफ में समान भोगौलिक प्रतिनिधित्व हो : भारत

संयुक्त राष्ट्र, 16 नवम्बर (ए)। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सचिवालय स्टाफ और शांतिरक्षण पदों पर नियुक्ति में क्षेत्रीय असमानताओं को लेकर चिंता जाहिर की है और समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर सक्रियता से विचार करने का आह्ववान किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव महेश कुमार ने बृहस्पतिवार को 'मानव संसाधन प्रबंधन' पर महासभा की पांचवी समिति (प्रशासनिक एवं बजट संबंधी) बैठक में कहा कि भले ही समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व को संयुक्त राष्ट्र मानव संसाधन प्रबंधन के केंद्र में रखता हो पर चुनौतियां अब भी बरकार हैं। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में कुल 38,000 कर्मचारी हैं जिनमें से 10 प्रतिशत से भी कम को वांछनीय प्रतिनिधित्व दिया गया है। यहां तक कि इन 3,600 पदों के लिए भी 64 देशों को बिना प्रतिनिधित्व वाले या अल्प प्रतिनिधित्व वाले देशों के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है। इन 64 देशों में से 50 विकासशील देश हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा वर्ष 2014 के बाद से बिना प्रतिनिधित्व वाले या अल्प प्रतिनिधित्व वाली श्रेणी में सदस्य देशों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साथ ही करीब 60 और विकासशील देश उनके वांछनीय प्रतिनिधित्व दर के निचले स्तर के समीप है और अल्प प्रतिनिधित्व की श्रेणी में पहुंचने के कगार पर हैं।

खशोगी हत्या मामला : अमेरिका ने 17 सऊदी नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया

वाशिंगटन, 16 नवम्बर (ए)। अमेरिका ने असंतुष्ट पत्रकार जमाल खशोगी की नृशंस हत्या में कथित रूप से संलिप्तता रखने वाले सऊदी अरब के 17 नागरिकों पर बृहस्पतिवार को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के लिए प्रतिबंध लगा दिया। खशोगी की तुर्की के इस्तांबुल में स्थित सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास में हत्या कर दी गई थी। अमेरिका ने सऊद अल कहतानी, उनके मातहत माहेर मुतरीब, सऊदी अरब के महावाणिज्य दूत मोहम्मद अल उतैबी और एक ऑपरेशन दल के 14 अन्य सदस्यों पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने बृहस्पतिवार को

कहा कि यह कार्रवाई शासकीय आदेश 13818 के तहत की गई है जिससे ग्लोबल मैगनीटस्काई ग्लोबल मैगनीटस्काई ह्यूमन राइट्स अकाउंटिबिलिटी एक्ट अमेरिका को यह अधिकार देता है कि वह दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने तथा भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए अहम कदम उठा सकता है।

सिंगापुर सम्मेलन में रोहिंग्या मामले में घिरीं आंग सान सूची

सिंगापुर, 16 नवम्बर (ए)। सिंगापुर में आयोजित एक सम्मेलन म्यामां की शीर्ष नेता आंग सान सू ची के लिए मुश्किलों भरा रहा। एक समय मानवाधिकार की पुरोधा रहीं सू ची के रोहिंग्या संकट से निपटने के तरीके को लेकर उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। सू ची ने रोहिंग्या समुदाय के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। इस मुद्दे पर सू ची की चुप्पी ने संयुक्त राष्ट्र सहित वैश्विक मानवाधिकार समुदाय के बीच उनकी साख गिराई है। संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं का कहना है कि पिछले साल म्यामां की सेना द्वारा रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ चलाया गया अभियान नरसंहार के बराबर था। रोहिंग्या म्यामां में हिंसा से प्रभावित

होकर बड़ी संख्या में बांग्लादेश जाने वाला मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है। यह सप्ताह सू ची के लिए बुरी खबरें लेकर आया। सोमवार को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' ने रोहिंग्या के खिलाफ अत्याचारों पर सू ची की ''अनदेखी'' के कारण उनसे सर्वोच्च सम्मान वापस ले लिया। इसी संगठन ने सू ची को उनके लोकतंत्र के लिए संघर्ष के चलते वैश्विक पहचान दिलाई थी। एक दिन बाद, सिंगापुर में एक क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्हें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। आसियान की बैठक में मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने सू ची की निंदा की।